

# सांध्य दैनिक

# 4PM

[www.4pm.co.in](http://www.4pm.co.in) [www.facebook.com/4pmnewsnetwork](https://www.facebook.com/4pmnewsnetwork) [@Editor\\_Sanjay](https://twitter.com/Editor_Sanjay) [YouTube @4pm NEWS NETWORK](https://www.youtube.com/4pm NEWS NETWORK)



इंसान की डाइट का हर एक तत्व  
उसके शरीर पर असर डालता है  
और किसी न किसी तरह उसे  
चेंज करता है और इही बदलावों  
पर उसका पूरा जीवन निर्भर करता है।

-हिप्पोक्रेटीस



जिद... सच की

• तर्फ़: 9 • अंक: 211 • पृष्ठ: 8 • लखनऊ, बुधवार, 6 सितम्बर, 2023

कोको गॉफ़ अमेरिकी ओपन के... | 7 | 24 का चुनाव है, मैदान में अभी... | 3 | राष्ट्रीय पहचान भाजपा की निजी... | 2 |

## 4PM के यूट्यूब की एक और कामयाबी

# सब्सक्राइबर हुए पंद्रह लाख, एक महीने में नौ करोड़ से ज्यादा व्यूज के साथ रखा इतिहास

» जुलाई में हासिल  
किया था  
दूसरा स्थान

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क  
लखनऊ। धीरे-धीरे जन-जन के बीच  
में लोकप्रिय होते जा रहे 4PM चैनल  
ने फिर एकबार आसमान को छू लिया  
है। जनता तक सच को बेबाक तरीके  
से पहुंचाने वाले लोकप्रिय चैनल ने 15  
लाख सब्सक्राइबर जोड़कर नया मील  
का पथर गढ़ा है। यहीं नहीं चैनल ने  
एक महीने के भीतर नौ करोड़ व्यू  
हासिल कर इतिहास रच दिया है।

इससे पहले डेटा विग्रह के जुलाई  
महीने के यूट्यूब के ऑकड़े जारी किए  
थे जिसमें 4PM को जुलाई माह में  
72.3 मीलियन लगभग साढ़े सात  
करोड़ व्यू मिले थे। इसी के साथ वह  
देश भर में दूसरे स्थान पर पहुंचा था।

इस उपलब्धि से 4PM के  
संपादक संजय शर्मा गदगद हैं।  
उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए

सब्सक्राइबर के साथ  
लगातार बढ़  
रही लोकप्रियता

सा और देश की सचिवालयों वाला 4PM  
न्यूजैनल आप दिन सफलता की नई  
बुलियों को छू रख रहा है। दिन एवं दिन यूट्यूब की  
दुनिया में आज एक अलग गुमान स्पष्टित  
कर रहा है। ये सच संबंधी हो रहे हैं सिर्फ  
उसके सच दिखाने और आज के समय में सा  
से साकाल करने की कठिनीयता की जगह से।  
4PM वो सची खबर दिखाता है जो आपको ये  
कथित में स्ट्रीग मीडिया के बैनल नहीं  
दिखाता। इसीलिए लोग इस चैनल को अधिक  
से अधिक देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं।

कहा कि मैंने सपने में  
भी नहीं सोचा था  
कि मेरे चैनल को  
लोग इतनी ऊँचाई पर  
पहुंच देंगे। अपनी जिद  
सच की के स्लोगन को  
सत्य चरित्रार्थ करने में  
जुटे इस लोकप्रिय चैनल  
ने भारत के बड़े-बड़े

यूट्यूब चैनल को जुलाई में  
पछाड़ दिया था। अपनी खबरों  
से सच दिखाने में अग्रणी  
4PM ने व्यू में 72.3  
मीलियन के आंकड़े का छू  
लिया था। इस चैनल से केवल  
डीबी लाइव ही आगे था  
जिसके 100 मीलियन से  
ज्यादा व्यू थे। सबसे  
लोकप्रिय पत्रकार  
रविश कुमार आठवें  
स्थान पर थे।

15  
लाख सब्सक्राइबर

एक बार फिर  
आप सभी  
का हृदय से  
आभार!

15 लाख... कभी सोचा नहीं था  
कि आपका प्लाय गेरी टिंगी में  
इतनी जर्दी को मुकाम ले  
आएगा, लगभग 10 दिन में  
एक लाख नए लोग मेरे परिवार  
से जुड़ जाते हैं, दुनिया भर से आ  
रहे गेल और प्लाय गेरी सेटिंग  
जीवन में एक नई कोई भर्ते  
रहे हैं, एक नहीं ने अगर आपके  
चैनल पर नौ कोड से  
जाग रायूं जा जाते थे  
यान्त्रिक से कग नहीं, ये सब  
आपके भाग्यों के कारण संभव  
हुआ है, इसे बताए रिएक्या, यारी  
मीरी सबसे बड़ी पूँजी है, यकीन  
रिएक्या कोई नी ताकत, कोई  
नी डर नुज़ुक सब बोलने से नहीं  
होक सकता योकि यहीं गेरी  
ताकत है, एक बार फिर आप  
सभी का हृदय से आभार।

दबाव में कभी नहीं  
झुका 4PM

4PM ने यहां तक पहुंचने में काफी मेहनत की व कई<sup>1</sup>  
मुरिकालों का सामना किया है। आए दिन सा से सवाल  
करना और देश के हुमारों पर सवाल उठाना। 4PM के  
लिए भी काफी मुरिकालों भरा रहा है। 4PM और संजय  
शर्मा की आवाज को दबाने का सा द्वारा कई बार प्रयास भी  
किया गया। लेकिन वो कहते हैं कि कि सच को कभी भी  
दबाया नहीं जा सकता और सच की यादी ताकत होती है कि  
जो भी सच को कहता है या बोलता है वो सफलता को हासिल  
कर ही लेता है। 4PM ने भी ये कहके दिखाया है। 4PM  
और संपादक संजय शर्मा की आवाज को दबाने के लिए या  
कुछ नहीं किया गया। 4PM के ऑफिस पर पर्यावर किया गया।  
यहां तक की बम से उड़ाने का भी प्रयास किया गया।

लेकिन संजय शर्मा नहीं डरे और 4PM को लेकर इसी  
तरह से सा से और साधीरों से सवाल करते रहे और अभी  
भी उनके सा से सवाल जारी है। कई बार 4PM के चैनल  
को भी सरकार द्वारा बंद कराया गया, ताकि वो इसके जरिए  
सच को दबा सकें और संजय शर्मा की आवाज को दबा सकें।  
लेकिन यहां भी सरकार को सिर्फ नियता ही द्वारा लगी।

## धोखे से धर्मात्मक रामनाथ को मांग वाली जनहित याचिका खारिज

» सुप्रीम कोर्ट ने कहा-  
अदालत सरकार को  
परमादेश की रिट कैसे  
जारी कर सकती  
□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने  
बुधवार को धोखे से  
धर्मात्मक रामनाथ को  
मांग वाली जनहित  
याचिका खारिज कर दी है।  
दरअसल, याचिका  
में मांग की गई  
थी कि केंद्र  
सरकार को  
आदेश दिया

जनहित  
याचिका कर्नाटक  
के जेरोम एंटो ने  
दावर की  
थी

जेरोम एंटो ने दावर की थी। जेरोम  
एंटो की ओर से पेश वकील ने शीर्ष  
अदालत में कहा कि हिंदुओं और  
नाबालिगों को निशाना बनाया जा रहा  
है और उनका धोखे से धर्म परिवर्तन  
किया जा रहा है। पीठ ने कहा कि यह  
किस तरह की जनहित याचिका है?  
जनहित याचिका एक दूल यानी  
हथकंडा बनकर रह गई है और हर  
कोई इस तरह की याचिकाएं लेकर आ  
रहा है। याचिकाकर्ता के वकील ने  
पूछा कि इस तरह की शिकायत लेकर  
कहा जाना चाहिए। इस पर पीठ ने  
कहा कि हम सलाहकार क्षेत्राधिकार में  
नहीं हैं। अगर हाल ही में कोई ऐसा  
मामला आया है या किसी पर किसी  
पर मुकदमा चलाया गया है तो हम  
उस पर विचार कर सकते हैं। इसके  
बाद शीर्ष अदालत की पीठ ने जनहित  
याचिका को खारिज कर दिया।

## एक देश-एक चुनाव, आज होगी समिति की पहली बैठक

» पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद  
के घर जाटेंगे सदस्य

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। एक देश-एक चुनाव के लिए केंद्र  
सरकार की तरफ से गठित की  
गई कमेटी की आज पहली  
बैठक होगी। बताया गया है कि  
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद  
के घर पर ही उनकी अध्यक्षता  
में यह मीटिंग हो सकती  
है। समिति के सदस्य  
दोपहर बाद इस  
बैठक में हिस्सा लेने  
के लिए जुट सकते हैं।  
कानून मंत्रालय के मुताबिक,  
इस समिति का नेतृत्व पूर्व  
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे।  
समिति में गृहमंत्री अमित  
शाह, राज्यसभा में विपक्ष के

विशेष आमत्रित सदस्य के स्वप्न  
में भाग लेंगे मेघवाल

एक सरकारी अधिकृतानां में कहा गया है कि कानून मंत्री  
अर्जुन गण नेश्वराल विशेष आमत्रित सदस्य के रूप में उच्च  
स्तरीय समिति की बैठकों में भाग लेंगे। समिति का गठन पांच  
राज्यों में विभागसमान चुनावों से कुछ महीने पहले और अगले  
साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले किया गया है।  
संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जारी ने शुक्रवार को समिति के  
गठन की जानकारी दी थी।

पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त  
आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह,  
लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष विशेष  
कार्य सभा के पूर्व अध्यक्ष विशेष  
संजय शर्मा और अधिकारी रामेश  
साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त  
संजय कोठारी शामिल हैं। वहीं, कांग्रेस  
नेता अधीर रंजन चौधरी आमंत्रण के  
बावजूद इस समिति में शामिल होने से  
इनकार कर चुके हैं।



# ‘राष्ट्रीय पहचान भाजपा की निजी प्रॉपर्टी नहीं’

## » राघव चड्हा बोले- केंद्र सरकार का यह फैसला देश विरोधी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा  
सांसद राधव चड्हा ने कहा कि केंद्र सरकार  
का यह फैसला देश विरोधी है। केंद्र  
सरकार ने इस मुद्दे को उठाकर एक बहस  
छेड़ दी है। लोगों की राष्ट्रीय पहचान  
भारतीय जनता पार्टी की निजी प्रॉपर्टी नहीं  
है। भाजपा ऐसा कैसे कर सकती है। आप  
के वरिष्ठ नेता ने कहा कि भाजपा ने हाल ही  
में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट  
ऑफ भारत जी 20 समिट के निमंत्रण पत्र  
पर लिखा गया है। बीजेपी इंडिया को डाउन  
कैसे कर सकती है। देश किसी राजनीतिक  
पार्टी से संबंध नहीं रखता है। इसका संबंध

135 करार का बना रहा है।  
जिसे वह अपनी इच्छानुसार बदल सके। इससे पहले कांग्रेस के राज्यसभा संसद जयराम रमेश ने दावा किया कि राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को जी20 राष्ट्रिभोज के लिए सामान्य भारत के राष्ट्रपति के बजाय भारत के राष्ट्रपति के नाम पर निमंत्रण भेजा है।

## कांग्रेसियों को एक परिवार के गुणगान से मतलब : नड़ा

» भारत माता की जय नारा  
रोकने पर कांग्रेस नेता  
आराधना को बीजेपी ने घेरा

□ □ □ 4पीएम न्यूज नेटवर्क



जयपुर। कांग्रेस नेता और राजस्थान पर्यवेक्षक आराधना मिश्रा भारत माता की जय के नाम सुनकर भड़क गई। उन्होंने कार्यकर्ताओं को कढ़ी फटकार लगाई। साथ ही कहा कि कांग्रेस किंजिंदाबाद के अलावा भारत माता की जय का नारा लगाया तो ये अनुशासनहीनता होगी। अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसे भाजपा नेताओं ने शेयर पर कांग्रेस पर हमला बोला है।

भाजपा अध्यक्ष जेपी नडुवा ने भी इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। नडुवा ने एकस (ट्वीट) कर कहा कि कांग्रेस को भारत की जय के नारे लगाना शुरू कर दिए। इसके बाद वहां मौजूद कांग्रेस पर्यवेक्षक आराधन मित्रा भड़क गई।

## घोसी चुनाव में जीत के अपने-अपने दावे

» सपा और भाजपा के बीच कांटे का मुकाबला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। धोसी विधानसभा उप चुनाव के लिए मंगलवार को हुए मतदान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) बनाम इडिया के बीच कांटे का मुकाबला हुआ है। हालांकि भाजपा और समाजवादी पार्टी के तमाम प्रयासों के बावजूद मतदान 51 प्रतिशत तक ही पहुंचा। भाजपा के समर्थित माने जाने वाले नोनिया चौहान, राजभर, निषाद और कुर्मी मतदाताओं ने भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।

वर्हीं सपा के परंपरागत बोट बैंक मुस्लिम और यादव समाज के साथ सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के सजातीय ठाकुर मतदाताओं ने भी पूरे जोश से मतदान कर मुकाबले को न केवल रोचक बल्कि कांटे का बनाया। बरहाल यह माना जा रहा है कि जो भी दल दलित मतदाताओं में सेंध जाइ जा रहा था। मुस्लिम और यादव मतदान नहीं करने भाजपा प्रत्याशी दारा फ़ सजातीय नोनिया चौहान के साथ राजभर और जो के मतदाताओं ने भी मतदान किया। इन ज बस्तियों के मतदान बृश



लगाने में जितना सफल रहेगा बाजी  
उसके के हाथ लगेगी। उपचुनाव को  
लेकर विपक्ष की ओर से आशंका  
जताई जा रही थी कि उनसे जुड़े  
मुस्लिम और यादव मतदाताओं का  
मतदान नहीं करने दिया जाएगा।  
भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के  
सजातीय नोनिया चौहान मतदाताओं  
के साथ राजभर और निषाद समाज  
के मतदाताओं ने भी पूरे जोश से  
मतदान किया। इन जातियों से जुड़ी  
बस्तियों के मतदान बृहों पर भी लंबी

लंबी कतारें देखने को मिली।  
जातीय समीकरण के लिहाज से उप  
चुनाव में पूरा दारोमदार राजभर,  
नेनिया चौहान और निषाद समाज के  
मतदाताओं पर है। उपचुनाव में दलित  
मतदाताओं ने भी मतदान में बढ़ा-  
चढ़कर हिस्सा लिया है। दोनों ही दलों  
की ओर से दलितों का मतदान  
प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया गया।  
दलितों में खटीक और धोबी समाज  
का रुझान भाजपा की ओर दिखा।  
लेकिन दलित वर्ग में जाटव मतदाता

विषयक  
51

**विपक्ष ने लगाया  
सरकारी मशीनरी के  
दृष्टिप्रयोग का आरोप**

विषय की ओर से सत्तापथ पर साकारी महीना  
का दृश्योग कर उनके मतदाताओं  
का भयनीति करने का आपे ने  
लगाया गया। लैकिन मंगलवार  
को हुए मतदान में मुसिलम, याद  
और राशुर बहुल इलाकों  
मतदान के द्वारा पर मारी गई देखते  
को निला। शुरुआती दौर में प्रवाह  
पत्र और आधार कार्ड के नाम पर  
मतदातों को प्रेशन करने की शिकाया  
निला। लैकिन उसके बाद मतदान सामाजिक  
त्वयवस्था के तहत घलता रहा। बालाक मुसिलम  
बहुल इलाकों में नतदान प्रतिशत थोड़ा कम रहा  
है। साथ के गोट बैंक से जुड़ी अच्युत रामपुराण  
जग्निकर मतदान किया। आजमार्क और रामपुराण  
लोकसंसाधन पर चुनाव या रामपुराण सभा उ  
चुनाव जैसी स्थिति नहीं रहने से सपा मुकाबले ते  
मजबूती से बनी दृष्टि

सबसे अधिक हैं। जाटव मतदाताओं का दोनों ही दलों की ओर रुझान दिखा।

## आरएसएस और भाजपा के मन में कंठ : संजय सिंह

आप नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह और आप की मुख्य प्रवत्ति प्रियंका कवठक ने कहा कि जोटी सरकार संविधान से इंडिया शाल को हटाना चाहती है। इसकी थक्कात आरएसएस के प्रमुख जोहन मागरत ने की। इंडिया शाल को हटाकर अपनी सिर्फ़ भारत शाल का इस्तेमाल करेंगे। उन्नेने कहा कि जापा और आरएसएस ने बैरीचा नफरत फैलाने का काम किया है, लेकिन बासा सोहब ने वरिष्ठ सभाज से उत्कर देश का संविधान लिखा। इस बात की कुंठां आरएसएस और जापा के मन में है। वहीं केंजटीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार ने पिपली गढ़वाल इंडिया से डकर नाम में यह बदलाव किया है।

केंजटीवाल ने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों का है किसी एक पार्टी का थोड़ी है। देश का नाम बदल दो। ये देश के साथ गवारी है।

## यूपी विस में लालजी टंडन ने भी किया था समर्थन

मुलायम सिंह ने हिंदी के प्रोग्रेम पर बल देते हुए कहा कि संस्कृतीय कार्यक्रमी सदन में प्रस्ताव लाएं और उसे पारित करके केंद्र सरकार को भेज दिया जाए कि जहाँ सविधान में इंडिया इन भारत लिखा है, वहाँ भारत इन इंडिया लिख दिया जाए। इस पर लालजी टंडन ने सुनाता दिया कि सविधान में संशोधन का प्रस्ताव है, इसे परिवहत लाया जाना चाहिए। इसके बाव तात्पुरीलीन सीधी की ओर से रखे गए प्रस्ताव को सर्वसमर्थी से संतुष्टी किया गया। ये प्रस्ताव था-यह सदन केंद्र सरकार से संतुष्टी कराया जाए कि सविधान के भाग-1 के अनुच्छेद-1 (लैन एं टर्टीटीटी ऑफ कूनियन) में इंडिया टैट इन भारत के स्थान पर भारत टैट इन इंडिया रखने हेतु सविधान में आवश्यक संशोधन करें।

**इंडिया नाम पर विवाद सत्ता पक्ष व विपक्ष की मिलीभगत : मायावती**

लखनऊ। बस्या सुनीलोंगामीयाती ने शुभगार को मौदिया को संबोधित करते हुए कहा कि देश के नाम इंडिया पर विवाद सत्ता पक्ष और विपक्ष की मिलीभगत है। वह मौदिया को संबोधित कर रही थी। बता दें कि केंद्र सरकार ने देश के नाम इंडिया की जगह माराटा को प्रणाली में लाने का शुरूआती कर दी है। इसे लोकवाचन पुस्तक 2024 के अनुसार विद्युती महाराष्ट्रान के नाम इंडिया से भी जोड़कर देशा जा रहा है। कांग्रेस ने इसे किया है कि गोदी सरकार विपक्षी गठबंधन से इतना डर है कि अब देश का ही नाम बदल देता वायदा है। जबकि संविधान के पहले ही अनुच्छेद में लिखा है कि इंडिया टैट डम आगती-



# 24 का चुनाव है, मैदान में अभी और दांव हैं

- » जी20 सम्मेलन के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट आफ भारत पर रार
  - » भाजपा व मोदी सरकार पर पूरे विपक्ष का हमला

नई दिल्ली। जी-20 सम्मेलन के रात्रिभोज कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने पर गाजनीति शुरू हो गई है। विषयकी पार्टीयां इसे लेकर सरकार पर निशाना साध रही हैं। मोदीवाले सरकार द्वारा पत्र में प्रेसिडेंट आफ इंडिया सही है। पर या गलत ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। पर इसमें कोई शक नहीं भाजपा पूरी तरह से 2024 चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पहले यूसूसी फिर वन नेशन वन इलेक्शन और अब इस पत्र में भारत का इस्तेमाल करके भाजपा ने विषय इंडिया को धेरने का प्रयायस किया है। आगे आने वाले समयमें यह मुद्दा और गरमाएगा। दरअसल कांग्रेस ने मंगलवार (5 सितंबर) को आरोप लगाया कि राज्यों के संघ पर मोदी सरकार हमला कर रही है, जिस इनविटेशन को लेकर बवाल मचा है, वो जी20 सम्मेलन के डिनर का कार्यक्रम है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दुनिया भर के राष्ट्रपति और कई राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेने वाले हैं, इस डिनर के इनविटेशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है।

वहीं सर्विधान के अनुच्छेद में हू-ब-हू वर्णित है। लेकिन बात इसकी व्याख्या की है। सवाल है कि क्या दोनों कांग्रेस नेताओं आर्टिकल 1 को जिस रूप में पेश कर रहे हैं, वो सही है? राहुल गांधी संसद में भी कह चुके हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं, राज्यों का एक संघ है। इस बयान पर भी जमकर बवाल मचा था और गंभीर चर्चा भी हुई थी। तब सत्ताधारी बीजेपी ने राहुल गांधी पर क्षेत्रीय भावनाएं भड़काकर देश को कमज़ोर करने और अलगाववाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। सवाल तो बनता ही है कि कांग्रेस नेता बार-बार भारत के राज्यों का संघ होने पर जोर क्यों देते हैं? क्या वो यह कहना चाहते हैं कि हर राज्य स्वतंत्र है और भारत महज उनकी छतरी है, ठीक यूरोपियन यूनियन की तरह?



**इसमें नया क्या है सभी जानते हैं इंडिया मतलब भारत : ममता**

परिचय बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर कहा कि उन्होंने (केंद्र सरकार) इंडिया का नाम बदल दिया है। जी20 के राष्ट्रियोज के निमंत्रण पत्र में इंगिलिश में भारत लिखा गया है। हम इंडिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। वहीं हिंदी में हम भारत का संविधान कहते हैं। हम सभी भारत कहते हैं और इसमें नया क्या है? लेकिन इंडिया नाम दुनियाभर में जाना जाता है, अब अचानक से क्या हो गया कि उन्हें देश का नाम बदलने की जरूरत पड़ गई? बंगाल सीएम ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया, भारत है लेकिन दुनिया हमें इंडिया के तौर पर जानती है।



**सरकार इतनी बेवकूफ नहीं की पूरी तरह से नाम बदल दे : थर्स्ट**

कांग्रेस ने भी सरकार के इस कदम की आलोचना की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया है कि जी20 के राक्षितों के लिए भेजे गए निमत्रण पत्र में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बदला गया है और उसकी जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जयराम रमेश ने कहा कि जो इंडिया था, वह राज्यों का संघ था लेकिन अब तो राज्यों के संघ पर भी हमला किया जा रहा है। थर्चर ने कहा कि सरकार इतनी बेकूफ नहीं होगी जो इंडिया नाम को पूरी तरह से हटा दे, जिसकी सदियों में एक ब्रांड वैल्यू बनी है।



**नाम बदलने का अधिकार किसी को नहीं : शरद पवार**

जी 20 के डिनर में राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर मध्ये बवाल के बीच अब शरद पवार ने इस मामले पर कहा कि किसी को भी देश का नाम बदलने का अधिकार नहीं है। शरद पवार ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे की बुधवार (6 सितंबर) को बुलाई गई बैठक में उन सभी पार्टीयों के प्रमुखों के साथ इस मुद्दे पर बातचीत होगी, जो इंडिया गढ़बंधन का हिस्सा हैं। 2024 के चुनाव में एनडीए के मुकाबले के लिए बने इस गढ़बंधन में 28 पार्टीयां शामिल हैं, शरद पवार ने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि सत्तारूढ़ दल देश से जुड़े एक नाम को लेकर क्यों परेशान है। एनसीपी चीफ ने ये बात उस वक्त कही।



क्या कहता है  
आर्टिकल

अनुष्ठेद 1 में भारत और इंडिया को लेकर यह कहा गया है। आर्टिकल 1 का शीर्षक संघ और उसका राज्य थेट है। इसमें कहा गया है। 1. संघ का नाम और राज्य थेट (1) भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा। (2) राज्य और उनके राज्य थेट वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दित हैं। (3) भारत के राज्यथेट में,-(क) राज्यों के राज्यथेट, (ख) पहली अनुसूची में विनिर्दित संघ राज्यथेट, और (ग) ऐसे अन्य राज्यथेट जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे।

# राजा भरत के नाम पर पढ़ा भारत

□ □ □

वैदिक सभ्यता (1500 ईसापूर्व, 600 ईसापूर्व) भारत को एक सनातन राष्ट्र माना जाता है क्योंकि यह मानव सभ्यता का पहला राष्ट्र था। श्रीमद्भागवत के पंचम स्कन्ध में भारत राष्ट्र की स्थापना का वर्णन आता है। भारतीय दर्शन के अनुसार सृष्टि-उत्पत्ति के पश्चात् ब्रह्मा के मानस पुत्र रत्यांभु मनु ने व्यवस्था सम्भाली। भारत शब्द से भारतीय उपमहादीप, भारत गणतंत्र, या वृहत्तर भारत आदि का आशय लिया जाता है। भारत के अग्रेजी नाम इण्डिया (इंडिया) की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है जो यूनानियों द्वारा चौथी सदी ईसा पार्ट से गठित में है। इण्डिया नाम पार्सी

पूर्व से प्रयत्नन म हा इडा नाम पुराना  
 अंग्रेजी में 9वीं सदी में और आधुनिक  
 अंग्रेजी में 17वीं सदी से मिलता है। जब  
 अंग्रेज भारत में आए उस समय हमारे देश  
 को हिन्दुस्तान कहा जाता था, हालांकि, ये  
 शब्द बोलने में उन्हें परेशानी होती थी,  
 ब्रिटिश सरकार को पता लगा कि भारत  
 की सभ्यता सिंधु घाटी है जिसे इंडस वैली  
 भी कहा जाता है। इस शब्द को लैटिन  
 भाषा में इंडिया भी कहते हैं, तो उन्होंने  
 भारत को विदिया कहना शुरू कर दिया।



लेकिन भारत या भारतवर्ष न

लेकिन भारत या भारतवर्ष नाम का समर्थन करने वाले ये सारे नेता उत्तर भारत या कहें कि हिंदी पट्टी के थे, जबकि भारत का विस्तार उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है, संविधान सभा में हर क्षेत्र, हर भाषा के लोग बैठे थे, हिंदी को राजभाषा मानने पर पहले ही बहुत घमासान हो चुका था, ऐसे में विदेशों से संबंधों का हवाला और देश में सबको एक सूख में जोड़ने की कोशिश करते हुए संविधान के अनुच्छेद एक मैं लिखा गया कि इंडिया अर्थात् भारत राज्यों का सघ होगा।

## इंडस से बना इंडिया

हमारे देश के बदलते नाम का एक इतिहास है। कहते हैं कि महाराज भरत ने भारत का संपूर्ण विस्तार किया था और उनके नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। मध्य काल में जब तुर्क और इरानी यहाँ आए तो उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया, वो स का उत्तराधिकार ह करते थे और इस तरह से सिंधु का अपभ्रंश हिंदू हो गया, उन्होंने यहाँ के निवासियों को हिंदू कहा और हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान का नाम मिला। सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस भी था, इस नदी के किनारे विकसित सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाई। सिंधु नदी का इंडस नाम भारत आए विदेशियों ने रखा। सिंधु सभ्यता के कारण भारत का पुराना नाम सिंधु भी था, जिसे यूनानी में इंडो या इंडस भी कहा जाता था। जब ये शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो बदलकर इंडिया हो गया।

## नाम को लेकर संविधान सभा में हुई थी चर्चा

14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को जब भारत अपने भाग से मुलाकात कर रहा था, तो वो घड़ी हिंदुस्तान के लिए सदियों के संघर्ष और तपस्या का पुण्य फल भी थी। सदियों के बाद मिली आजादी के बाद नया भारत फैसे चलेगा, इसके बया कायदे-कानून होंगे इसे लेकर एक संविधान भी बनाया जा रहा था। संविधान सभा में देश के नाम पर सवाल उठा कि दुनिया के सबसे



झापटगा कमटा के अद्यता छावटर  
भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि इसको आधे घंटे में स्वीकार कर  
लिया जाए, लेकिन दूसरे सदस्यों में नाम को लेकर असहमति थी  
जो चाहते थे कि इडिया और भारत जैसे शब्दों के रिश्तों को  
समझ लिया जाए। इस बहस में सेठ गोविंद दास, कमलापति  
त्रिपाठी, श्रीराम सहाय, हरगोविंद पंत और हरि विष्णु कामथ जैसे  
नेताओं ने हिस्सा लिया। हरि विष्णु कामथ ने सुझाव दिया कि  
इडिया अर्थात् भारत को भारत या फिर इडिया में बदल दिया  
जाए। लेकिन उनके बाद सेठ गोविंद दास ने भारत के ऐतिहासिक  
संदर्भ का हवाला देकर देश का नाम सिर्फ भारत रखने पर बल  
दिया। इस पर बीच का रास्ता कमलापति त्रिपाठी ने निकाला,  
उहोंने कहा कि इसका नाम इडिया अर्थात् भारत की जगह भारत  
अर्थात् इडिया रख दिया जाए। हरगोविंद पंत ने अपनी राय रखते  
हुए कहा कि इसका नाम भारतवर्ष होना चाहिए, कुछ और नहीं।



Sanjay Sharma

f editor.sanjaysharma  
t @Editor\_Sanjay

जिद... सच की

# भारत की विविधता पर न हो हमला

इसे समझते हुए स्वतंत्रता आंदोलन संघर्ष उपरांत राष्ट्र निर्माण के लिए संविधान समिति में सहमति/असहमति के विचारों को समृद्धित प्रतिनिधित्व दिया गया। जिससे भारत की अनेकता में एकता की भावना आकार ले सके। संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान में लोकतान्त्रिक व्यवस्था संचालन हेतु प्रत्येक पांच वर्ष केंद्र और राज्य में चुनाव की व्यवस्था की गई है। संविधान में संघ का नाम भारत अर्थात इंडिया को राज्यों का संघ कहा गया है। इसका ढांचा संघीय है। इसके साथ ही केंद्र और राज्य की व्यवस्था के पृथक्करण हेतु सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। जिससे केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक शक्तियों एवं सीमाओं के बीच टकराहट से बचा जा सके। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में महामहिम राष्ट्र पति को प्रथम व्यक्ति के रूप में स्थान प्राप्त है। जिसका निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। जबकि प्रधानमंत्री संसद के मंत्रिमंडल का नेता होता है जिसका निर्वाचन परंपरागत मतदान प्रणाली से होता है। राज्यों में यह व्यवस्था महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के रूप में दिखाई देती है। केंद्र और राज्य के चुनाव जहां निर्वाचन आयोग करवाता है वहीं राज्यों में निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को राज्य निर्वाचन आयोग ही करवाता है। यह विश्लेषण इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि भारत में चुनाव का स्वरूप एकरूप नहीं है। स्वतंत्र भारत की संवैधानिक व्यवस्था में विविधता प्रभावी रूप है। राष्ट्रीय स्तर पर देश के अमूमन सभी प्रांतों का प्रतिनिधित्व देखने की मिलता है। राष्ट्र पति, उपराष्ट्र पति, प्रधानमंत्री सहित अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों की विविधता भारत को एक राष्ट्र के रूप में बांधे रहती है।

—  
—

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

केके तलवार

भारत को 'दुनिया का दवाखाना' कहा जाता है। भारत में बनी जेनेरिक दवाओं का निर्यात विश्वभर में होता है। 21वीं सदी के अरंभ तक देश में किसी दवा को पेटेंट उत्पाद के अनुसार न देकर उत्पादन प्रक्रिया के मुताबिक दिया जाता था। इससे भारतीय दवा उद्योग को पेटेंट का उल्लंघन करने का जेनिक उठाए बैगर दवाएं बनाने का मौका मिला। पहले से किसी और की बनी दवा के घटकों को खोजकर उत्पादन करने की स्वदेशी क्षमता का क्रमिक विकास होता चला गया। आज हम दुनिया में जेनेरिक दवाओं के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता हैं, खासकर एचआईवी और एड्स या फिर अन्य जीवन रक्षक वैक्सीन। चूंकि जेनेरिक दवाएं वह होती हैं जिसके घटक हू-ब-हू ब्रांडेड दवाओं वाले होते हैं, इसलिए असर भी समान होता है।

जेनेरिक दवाओं की विकासता के पीछे मुख्य कारण है, इनकी कम कीमत क्योंकि इनको बाजार में उत्तरने से पहले जानवरों या क्लीनिक में इंसानों पर प्रयोग वाली महंगी और अनिवार्य प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। भाव में सस्ती होने के कारण विकासशील मुल्कों के लिए इनका बहुत महत्व है और इस तरह दुनिया का भला होता है। जब बात दवाओं की आए तो कहा जाता है कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। समाज में ऐसी धारणा भी है कि देश में उपलब्ध जेनेरिक दवाओं में कुछ घटिया हैं। क्या हैरानी इन चिंताओं के कारण मरीज जेनेरिक दवाओं से गुरेज करते हैं, इसलिए महंगी होने के बावजूद रुक्न ब्रांडेड दवाओं की ओर है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जन-औषधि दुकानों पर कम बिक्री है।

## प्रभावशाली- सुरक्षित भी हो जेनेरिक दवा

राष्ट्रीय दवा आयोग की हालिया अधिसूचना कि चिकित्सकों को केवल जेनेरिक दवाएं ही लिखकर देनी हैं, इसके पीछे मुख्य मंशा सही है। लेकिन इस फैसले ने उपलब्ध जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता वाले गंभीर विषय को भी आगे ला दिया है। चिकित्सकों की चिंताएं भी जायज हैं, जिसको मर्दिया ने काफी प्रकाशित किया। राष्ट्रीय दवा आयोग ने जेनेरिक दवाएं लिखने की अनिवार्यता पर फिलहाल अमल न करने का निर्णय लेकर सही किया है। तथापि, जेनेरिक दवाओं की ओर केंद्रित हुआ ध्यान प्राप्तिकर है। वास्तव में, जेनेरिक दवाओं का इस्तेमाल करवाने के पीछे उद्देश्य है कि रोगी का इलाज पर अपनी जेब से होने वाला खर्च घट सके और इसके लिए सरकार को गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं सुनिश्चित करवाने के हरसंभव उपाय करने चाहिए।

हमारे मुल्क में नकली अथवा घटिया दवाएं होना, कमज़ोर नियामक तंत्र की वजह से है। ऐसी दवाओं के नतीजे कई बार रोग में बहुत सी जटिलताएं पैदा हो जाती हैं। पिछले साल, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में भी ऐसे कई मामले हुए, एक उत्पादक की बनी प्रोपोफोल दवा से मौत तक हुई। गांम्बिया नामक देश में कुछ बच्चों

## समावेशी लोकतंत्र के विचार को संबल

डॉ. डॉ. डॉ. डॉ.

विश्व में लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाने वाला भारत राष्ट्र न केवल सबसे पुराना लोकतंत्र है बल्कि एक परिपक्व लोकतंत्र भी है। भारत में लोकतंत्र की जड़ें चौथी शताब्दी से ही देखी जा सकती हैं। तंजावुर के पथर के शिलालेख इसका जीवंत प्रमाण हैं। कलिङ्ग और लिच्छवि काल के दौरान मौजूद सामाजिक व्यवस्थाओं के साक्ष्य भी भारत के लोकतान्त्रिक इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताते हैं।

भारत में 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' का विचार चुनाव-चक्र को इस तरह से संरचित करने का है कि लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनाव 'समकालिक' व 'समक्रमिक' हों जिससे चुनी हुई सरकारें एक साथ बैठें और देश को साधनों-सासाधनों और धनशक्ति-श्रमशक्ति के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक परिणाम प्राप्त करने हेतु दूरदर्शीपूर्ण योजना को व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए सकारात्मक विचार करें।

वर्ष 1947 में आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। इसके बाद कुछ राज्यों की विधानसभाएं पहले भंग होने के चलते यह व्यवस्था टूटी चली गई। ध्यानाकर्षण बात यह है कि वर्तमान 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' का प्रस्ताव लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ ही नगरपालिकाओं व पंचायतों के चुनाव कराए जाने की बात का अंगीकृत करने का उल्लेख कर रहा है। इस परिदृश्य में यहां यह उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जर्मनी, हंगरी, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, स्पेन, स्लोवेनिया, अल्बानिया, पोलैंड, बेल्जियम और स्वीडन जैसे देशों में अज भी एक ही बार चुनाव कराने की परंपरा है।

वर्तमान में, जब भी सरकार का कार्यकाल समाप्त होता है या जब भी विभिन्न कारणों से सदन भंग होता है तो चुनाव का बोझ राजकोष पर पड़ता है। हर साल देश में औसतन 4 से 6

विधानसभा चुनाव होते हैं जिससे प्रशासनिक, नीतिगत मामले प्रभावित होते हैं। अगरानीय वित्तीय लागत के चलते लगातार चुनाव करना 'सफेद हाथी' को पालने जैसा शौक साबित हो गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक चुनाव के दौरान सरकारी-तंत्र चुनावी प्रक्रिया और संबंधित कार्यों के कारण अपने नियमित कर्तव्यों से चूक जाता है। चुनावी बजट में इन लाखों मानव-घंटे की लागत की गणना की ही नहीं जाती। चुनावों के चलते 'आदर्श आचार संहिता' सरकार की कार्यप्रणाली को भी बुरी तरह से प्रभावित करती है, क्योंकि चुनावों की



दल देश के किसी न किसी हिस्से में लगातार होने वाले चुनाव लड़ रहे होते हैं और इस प्रकार उनके द्वारा किए जाने वाले चुनावी खर्च पर सीमा निर्धारित करना न केवल मुश्किल है बल्कि असंभव भी। कहने की जरूरत नहीं है कि 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' की अवधारणा से चुनावों में चल रहे काले धन के इसेमाल और भ्रष्टाचार पर काफी हद तक अंकुश लाएगा। एक भारत की परिकल्पना के चलते जब माल एवं सेवा कर 1 जुलाई, 2017 से सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में 'एक राष्ट्र-एक कर' के सिद्धांत के रूप में प्रणालीबद्ध व सफलतापूर्वक स्थापित हो गया है तो चुनावी सुधार और जीवोंद्वारा के लिए इस प्रस्ताव से पहले क्यों? बार-बार होने वाले चुनाव राजनीतिक दलों और राजनेताओं को सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने व सामाजिक समरसता को भंग करने का मौका देते हैं जिसके कारण अनावश्यक तानव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक चुनाव की सोच में सामाजिक समरसता का भाव टपकता है।



प्रभावशाली और सुरक्षित पाइ जाएं। वहां किसी जेनेरिक दवा को मंजूरी पाने के लिए सख्त अवलोकन प्रक्रिया से गुरना पड़ता है। अमेरिका का ड्रग एंड फूड एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) विभाग तो दवा उत्पादन कारखानों का निरीक्षण तक करता है ताकि सुनिश्चित हो सके कि दवाएं सर्वोत्तम मानकों की पालना करके बनाई जा रही हैं। इससे मरीज का जेनेरिक दवाओं पर परीत तरह भरोसा बनता है। अकांडे खुद बताते हैं आईएमएस संस्थान के मुताबिक जेनेरिक दवाओं ने 2009-19 के बीच दस सालों में अमेरिकी स्वास्थ्य तंत्र के लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर बचाए।

इससे सबक लेते हुए हमें अपना नियामक तंत्र मजबूत करना चाहिए। जब तक सख्त गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली स्थापित नहीं हो जाती और गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित न हो तब तक दवाएं कम असरकारक और उनसे रोगी में गंभीर सलग्न जटिलताएं पैदा होने का दोहरा खतरा बना रहेगा। हमारी उत्पादन निर्देशावली का पुनरावलोकन और प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करवाने की फैरन जरूरत है। इसके लिए परीत तरह प्रशिक्षित व्यावसायिक जांचकर्ताओं से सज्जित परीक्षण शालाओं वाला यथेष्ट तंत्र सुनिश्चित करना होगा। वैधानिक एवं अन्य सुरक्षा मानकों के पालन के लिए कड़ी निगरानी अहम होगी। कानूनी एवं नियामक तंत्र इस तरह बनाया जाए जो कि दवा निर्माताओं में स्व-पालन और स्व-नियंत्रण को प्रोत्साहित करे और ठीक इसी वक्त उल्लंघनकर्ताओं या गलत आचरण करने वालों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की शक्ति भी उसके पास हो। भारत में दवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जिम्मेवार केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) को और मजबूत एवं शक्तिशाली बनाना हो



# कम बजट की फिल्मों के चलते आलिया के साथ नहीं करता काम : अनुराग

अ

नुराग कश्यप मशहूर फिल्म निर्माताओं में से एक हैं। उन्होंने कई दमदार फिल्मों को बड़े पर्दे पर उतारा है। अनुराग की फिल्मों का बजट बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन उनकी फिल्में लोगों को काफ़ी पसंद आती है। अब हाल ही में, अनुराग ने एक इंटरव्यू में आलिया के साथ काम करने को लेकर बड़ा बयान दिया है। हाल ही में, जूम को दिए एक इंटरव्यू में गैंगस और वासेपुर के निर्देशक अनुराग कश्यप ने आलिया भट्ट के बारे में खुलकर बात की और बताया कि कैसे वह उनके काम के बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने अभिनेत्री को देश के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में से एक बताया। अनुराग बोले— जब उन्हें आलिया का काम पसंद

आता है, तो वह हमेशा उनसे संपर्क करते हैं, लेकिन जब उनका काम पसंद नहीं आता, तो वह चुप रहते हैं। आगे बात करते हुए

उन्होंने कहा कि चूंकि वह

कम बजट की फिल्मों बनाते हैं, इसलिए वह आलिया जैसे कलाकारों के साथ काम नहीं कर सकते। अगर यह मेरी फिल्म के बजट और गणितीयता को प्रभावित नहीं करता है तो मैं (उनके साथ काम करना) पसंद करूँगा, लेकिन इसे दूसरी तरफ से भी

आना होगा। इसके अलावा उन्होंने काम को लेकर कहा कि अगर कोई अभिनेता

इस हॉलीवुड फिल्म में नजर आएगी आलिया

उनके साथ काम करने से शिक्षिकरता है, तो वह

तुरंत पीछे हट

जाते हैं। मैं इच्छाधारी सोच में विश्वास नहीं करता और ना ही मैं एक से ज्यादा

बार एक्टर्स को अपने साथ काम करने के लिए कहता हूँ। अगर वो मुझे रिकॉर्ड में चेंज करने के लिए कहते हैं, तो मैं करता हूँ, लेकिन अगर वो शिक्षिकरते हैं तो मैं पीछे हट जाता हूँ।

वर्तोंकि अगर उनका दिल इसमें नहीं है, तो आप तुरंत रुक्कीन पर बता सकते हैं। आलिया ने बॉलीवुड में स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपने करियर की शुरुआत की है।

इसके बाद एक से बढ़कर एक कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। बॉलीवुड फिल्मों से लेकर हॉलीवुड में उनकी आने वाली फिल्म हार्ट ऑफ रसेन तक आलिया भट्ट ने एक लंबा सफर तय किया है। अनुराग कश्यप एक जाने-माने फिल्म निर्माता हैं। वो अक्सर सामाजिक और राजनीतिक जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखते हुए नजर आते हैं।

उन्होंने अभिनेत्री को देश के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में से एक बताया। अनुराग बोले— जब उन्हें आलिया का काम पसंद

किया कि उनके पिता सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनका बेटा अभिनेता बने। एकटर चाहते थे कि वह पढ़ाई करें। उन्होंने कहा, आप एक पल के लिए खुश होते हैं और काम न मिलने से दुखी होते हैं। मेरा मतलब है, पिताजी को 22 साल बाद गदर 2 मिली जो बॉक्स ऑफिस पर हिट

बॉलीवुड

करते हुए, एक यूजर ने लिखा, राजश्री अपने आप में एक भावना है... नई पीढ़ी को इस बैनर के तहत अपनी यात्रा शुरू करते हुए देखकर मैं कितना खुश हूँ। इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता! एक नई शुरुआत, नई कहानियां, नई कथाएं... अवनीश,

राजवीर और पलोमा को शुभकामनाएं। ट्रेलर पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए एक दूसरे यूजर ने लिखा, मैं बड़ात्या परिवार, विशेष रूप से अपनीश, राजवीर और पलोमा के लिए बहुत खुश हूँ! इस फिल्म के लिए सुपर दुपर उत्साहित हूँ।

सुपर दुपर उत्साहित हूँ।

गसाला

करते हुए, एक यूजर ने लिखा, राजश्री अपने आप में एक भावना है... नई पीढ़ी को इस बैनर के तहत अपनी यात्रा शुरू करते हुए देखकर मैं कितना खुश हूँ। इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता! एक नई शुरुआत, नई कहानियां, नई कथाएं... अवनीश,

राजवीर और पलोमा को शुभकामनाएं। ट्रेलर पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए एक दूसरे यूजर ने लिखा, मैं बड़ात्या परिवार, विशेष रूप से अपनीश, राजवीर और पलोमा के लिए बहुत खुश हूँ! इस फिल्म के लिए सुपर दुपर उत्साहित हूँ।

## पापा नहीं चाहते थे कि मैं एकटर बनूँ : राजवीर

**बॉ** लीवुड एकटर सनी देओल एक और जहां अपनी हालिया रिलीज फिल्म गदर 2 के जरिए बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। वहीं, दूसरी और अभिनेता के छाटे बैटे राजवीर देओल दोनों से एकिंग की दुनिया में कदम रख रहे हैं। बीते दिन यानी चार सितंबर को 'दोनों' का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। इस फिल्म का निर्देशन बी-टाइम के मशहूर डायरेक्टर सुरज बड़ात्या के बैटे जायर हो गई। इसके बारे में अवनीश इस फिल्म के जरिए निर्देशन की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। फिल्म में राजवीर देओल और पूरम ढिल्लों की बेटी पालोमा ढिल्लों लीड रोल में नजर आ रही हैं। ट्रेलर लॉन्च इवेंट में, राजवीर ने खुलासा

किया कि उनके पिता सनी देओल नहीं चाहते थे कि उनका बेटा अभिनेता बने। एकटर चाहते थे कि वह पढ़ाई करें। उन्होंने कहा, आप एक पल के लिए खुश होते हैं और काम न मिलने से दुखी होते हैं। मेरा मतलब है, पिताजी को 22 साल बाद गदर 2 मिली जो बॉक्स ऑफिस पर हिट

बॉलीवुड

करते हुए, एक यूजर ने लिखा, राजश्री अपने आप में एक भावना है... नई पीढ़ी को इस बैनर के तहत अपनी यात्रा शुरू करते हुए देखकर मैं कितना खुश हूँ। इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता! एक नई शुरुआत, नई कहानियां, नई कथाएं... अवनीश,

राजवीर और पलोमा को शुभकामनाएं। ट्रेलर पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए एक दूसरे यूजर ने लिखा, मैं बड़ात्या परिवार, विशेष रूप से अपनीश, राजवीर और पलोमा के लिए बहुत खुश हूँ! इस फिल्म के लिए सुपर दुपर उत्साहित हूँ।

गसाला

करते हुए, एक यूजर ने लिखा, राजश्री अपने आप में एक भावना है... नई पीढ़ी को इस बैनर के तहत अपनी यात्रा शुरू करते हुए देखकर मैं कितना खुश हूँ। इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता! एक नई शुरुआत, नई कहानियां, नई कथाएं... अवनीश,

राजवीर और पलोमा को शुभकामनाएं। ट्रेलर पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए एक दूसरे यूजर ने लिखा, मैं बड़ात्या परिवार, विशेष रूप से अपनीश, राजवीर और पलोमा के लिए बहुत खुश हूँ! इस फिल्म के लिए सुपर दुपर उत्साहित हूँ।

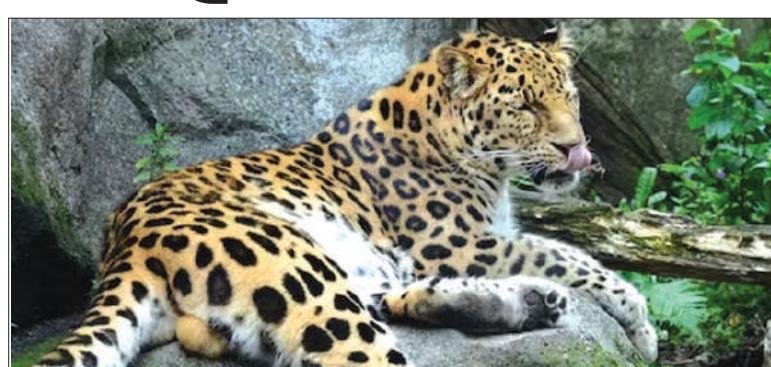


अजब-गजब

इस रहस्यमयी जगह पर तेंदुए और इंसान रहते हैं साथ-साथ

## 100 साल हो गए, पर नहीं हुई 3 अब तक कोई अनहोनी!

एक वर्क था, जब इंसान जंगलों में रहा करता था। वो खुद को खतरनाक जीवों से बचाना और उनके साथ रहना भी जानता था। हालांकि बाद में बस्तियां बर्सी और इंसानों और जानवरों के बीच की ये खास बॉलिंग खत्म हो गई। इंसानों ने कई जानवरों को पालतू बना लिया और जो जंगली रह गए, उनसे दूरी बनाकर रखने लगा। आपने कभी सोचा है कि आज के युग में भी क्या यानी और जानवर साथ रह सकते हैं? जब इंसान के हाथ में हथियार होते हैं, तो वो जानवरों का शिकार करता है और जब जानवर खुंखार होता है, तो वो इंसानों पर भी पड़ जाता है। हालांकि अपने ही देश में एक जगह ऐसी भी है, जहां इंसानों और खतरनाक शिकारी माने जाने वाले तेंदुओं के बीच ऐसा सामंजस्य बना हुआ है कि ये साथ-साथ रहते हैं। एक-दो नहीं बल्कि करीब 10 गांवों में सैकड़ों तेंदुओं ने इंसानों के साथ अपना घर बना रखा है। वेबसाइट ॲडिटी सेंट्रल के मुताबिक पिछले 100 साल से तेंदुए और इंसान एक साथ रह रहे हैं। इसके बीच प्यार और सामंजस्य ऐसा है कि उन्हें अपनी ही तरह समझने लगे हैं। इस कोई नुकसान नहीं पहुंचते। लोग भी उन्हें प्यार करते हैं। दिलचस्प ये भी है कि अगर वे उनके मरविशयों को भी खा लें, तो उन्हें वे बलि समझकर माफ कर देते हैं।



लोग हजारों साल पहले अफगानिस्तान के रास्ते इरान से होकर राजस्थान आ गए थे। भगवान की शिव की उपासना करने वाले ये लोग मानते हैं कि तेंदुए भगवान की ओर से भेजे गए उनके रक्षक हैं। वे कभी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते और लोग भी उन्हें प्यार करते हैं। दिलचस्प ये भी है कि अगर वे उनके मरविशयों को भी खा लें, तो उन्हें वे बलि समझकर माफ कर देते हैं।

दुनिया से 10 कदम आगे है जापान, वहाँ किंचन में ऐसे बर्तन होता है इस्टेमाल

भारत में चीन के बने सामान कभी बिकते हैं। ये क्रिएटिव के साथ साथ सर्सों तो होते हैं लेकिन टिकाऊ नहीं होते। इस वजह से चीन के बने सामान लंबे समय तक चल नहीं पाते। लोग भी इन्हें खरीदने से पहले कई बार सोचते हैं। खासकर किंचन के लिए बनाए गए सामान अगर चीन के बने हुए हैं तब तो सबसे ज्यादा अनसेफ माने जाते हैं। किंचन में बनाया जाने वाला खाना गर्म होता है। अगर कोई दुर्घटना हुई तो सीधे जापान पर खतरा बन सकता है। बात अगर तकनीकी की करें, तो चीन से भी काफ़ी आगे है जापान। जापानी तकनीक के आगे बुनिया के कई देश फेल हो जाते हैं। इसके बाद तेंदुए खुलासा करने के लिए एक ऐसी कड़ाही बनाई गई है जिसमें लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए जैस्मिन ने कहा कि इस दौरान, हेट इतनी ज्यादा थी कि इसने वास्तव में मुझे डिग्रेशन में डाल दिया था। एकट्रेस ने बताया कि बाद में उन्हें रेप की धमकियां भेजने वाले ऑनलाइन ट्रोलर्स की कोई पहचान नहीं है।



जापानी इन्वेंशन आगे आ रही है। इसके बाद तेंदुए खुलासा करने के लिए एक ऐसी कड़ाही बनाई गई है जिसम



# देश को अंधेरे में न रखे सरकार : विपक्ष

## विशेष सत्र के एजेंडे में पारदर्शिता बनाए, सोनिया गांधी लिखेंगी प्रधानमंत्री मोदी को पत्र

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आगामी सत्र के दौरान लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक को जल्द पारित कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगी। मामले की जानकारी रखने वाले नेताओं ने कहा कि कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद के आगामी विशेष सत्र में सरकार के एजेंडे को बताने और कई मुद्दों पर चर्चा करने की विपक्ष की मांग के बारे में उन्हें सूचित करने के लिए कहेंगी।

इससे पहले भारतीय गठबंधन के विपक्षी दलों ने मांग की कि सरकार 18 से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र के एजेंडे में पारदर्शिता बनाए रखे और



देश को अंधेरे में न रखे, साथ ही उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक को जल्द पारित

### भाजपा जनहित के मुद्दों को किनारे रखना चाहती है

भाजपा महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर, चीन, कैग्रिपोटेट, घोटाले और संस्थानों को कमज़ोर करना आदि जैसे प्रमुख मुद्दों को किनारे रखना चाहती है और हमारे लोगों को धोखा देना चाहती है। विपक्षी गढ़बंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्वेलूसिव अलायस (ईडिया) ने सरकार 18 सितंबर से बुलाए गए संसद के पांच दिवसीय विशेष सत्र में देश से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर सकारात्मक सहयोग करना चाहती है, लेकिन सरकार को यह बताना चाहिए कि बैठक का विशेष एजेंडा क्या है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे के आवास पर इंडिया के घटक दलों के दोनों सदनों के नेताओं की बैठक हुई जिसमें सत्र से जुड़ी रणनीति पर चर्चा की गई।

करने का भी आह्वान किया। वपक्षी दलों ने आगामी सत्र में एक साथ चलने और अडानी मुद्दे को भी उठाने का फैसला किया। उन्होंने भारत पार्टियों की पहली संयुक्त सार्वजनिक रैली मध्य प्रदेश में और अगली बैठक भोपाल में आयोजित

करने का भी निर्णय लिया। बैठक में खरगे और कई अन्य कांग्रेस नेताओं के अलावा द्रुमुक नेता टीआर बालू, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुले, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, जनता दल (यूनाइटेड)

के राजीव रंजन सिंह, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, शिवसेना (यूबीटी) के संजय राडत, समाजवादी पार्टी के एसपी हसन और कुछ अन्य दलों के नेता शामिल थे।

बैठक के बाद खरगे ने एक्स परोस्ट किया, सरकार पहली बार बिना एजेंडा बताए संसद का विशेष सत्र बुला रही है। किसी भी विपक्षी दल से न तो सलाह ली गई और न ही जानकारी दी गई। यह लोकतंत्र चलाने का तरीका नहीं है। उन्होंने दावा किया, हर दिन मोदी सरकार मीडिया में एक संभावित एजेंडा की कहानी पेश करती है, जिससे लोगों पर बोझ डालने वाले वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक बहाना तैयार किया जाता है।

## देश का हर व्यक्ति पढ़े संविधान : जयशंकर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। दिल्ली के प्रगति मैदान में नौ से दस सितंबर के बीच जी-20 बैठक होने जा रही है। इस बैठक के डिनर में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन से एक निमंत्रण पत्र भेजा गया है। निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। इस पर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है।

वहीं, विपक्ष जी-20 के लिए भारत सरकार द्वारा की गई तैयारियों पर भी हमला कर रहा है। इस पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि इंडिया भारत है और यह संविधान में लिखा है। मैं हर किसी को इसे (संविधान) पढ़ने के लिए कहूँगा। उन्होंने तैयारियों को लेकर कहा कि यह एक अलग युग है, यह अलग सरकार है और यह एक अलग विचार प्रक्रिया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि इंडिया भारत है और यह संविधान में लिखा है। मैं हर किसी को संविधान पढ़ने के लिए कहूँगा। जब आप भारत कहते हैं, तो एक अर्थ, एक समझ दिल्ली के लिए भवित्व में रहता है।



और एक अनुमान आता है और मुझे लगता है कि यही हमारे संविधान में भी परिलक्षित है। उन्होंने जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए सरकार द्वारा किए गए इंतजाम की विपक्ष द्वारा की जा रही आलोचना पर कहा कि अगर किसी को लगता है कि वे लुटियंस दिल्ली या विज्ञान भवन में अधिक सुविधाजनक महसूस कर रहे थे तो यह उनका विशेषाधिकार था। वहीं उनकी दुनिया थी और तब शिखर सम्मेलन की बैठकें ऐसे समय हुईं, जहां देश का प्रभाव संभवतः विज्ञान भवन में या उसके दो किलोमीटर (लुटियंस दिल्ली) तक में रहा हो।

## स्टालिन और प्रियांक के खिलाफ केस दर्ज



4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

रामपुर। सनातन धर्म पर टिप्पणी करने के मामले में तमिलनाडु के युवा कल्याण एवं खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन और कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियंक खरगे के खिलाफ रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। सिविल लाइंस क्षेत्र के एकता विहार कॉलोनी निवासी अधिवक्ता राम सिंह लोधी और आवास विकास कॉलोनी निवासी अधिवक्ता हर्ष गुप्ता ने एसपी को एक प्रार्थना पत्र दिया।

पुलिस ने बुधवार को कहा कि डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन और कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे के खिलाफ कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में यहां प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि स्टालिन पर सनातन धर्म को खत्म करने का आह्वान करने और खड़गे पर उनकी टिप्पणी का समर्थन करने के लिए मामला दर्ज किया गया है। एसपी अशोक कुमार शुक्ला ने बताया कि सिविल लाइंस कोतवाली में आईपीसी की धारा 153ए, 295ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ, किसने इसकी शुरुआत की : परमेश्वर



नई दिल्ली। सनातन धर्म पर विवादित बयान देने वाले नेताओं की लिस्ट लंबी होती जा रही है। उदयनिधि स्टालिन, प्रियांक खरगे के बाद अब कर्नाटक के गृह मंत्री और कांग्रेस नेता जी परमेश्वर ने सनातन धर्म को लेकर बेतुका बयान दिया है। परमेश्वर ने हिंदू धर्म को लेकर सवाल उठाए हैं। तुम्कुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए परमेश्वर ने कहा कि विश्व के इतिहास में कई धर्मों का जन्म हुआ है भारत में जैन और बौद्ध धर्मों का जन्म हुआ है। इस्लाम और ईसाई धर्म बाहर से यहां आए, लेकिन हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ और इसकी शुरुआत किसने की, यह आज भी एक सवाल है।

### वामपार्थियों के प्रभाव में हैं गृहमंत्री : बीजेपी

कर्नाटक के गृह मंत्री के बयान को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी विधायक सीएन अश्वथ ने कहा कि जी परमेश्वर वामपार्थियों के प्रभाव में हैं। वह हमारे देश भारत की संस्कृति और परंपरा को नष्ट करना चाहते हैं। जी परमेश्वर को एहसास होना चाहिए कि इस तरह का अंकार उनके लिए अच्छा नहीं है। उन्हें हमारे धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए।



## नासा ने चंद्रयान-3 लैंडिंग साइट की तस्वीर भेजी

» लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर (एलआरओ) ने खींची फोटो

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

वाशिंगटन। भारत के चंद्रयान-3 मिशन की हर तरफ चर्चा बनी हुई है। चांद की सतह पर सुरक्षित उत्तरने के बाद चंद्रयान-3 लगातार अपने काम में लगा हुआ है। नई-नई जानकारियां वैज्ञानिकों को मिल रही हैं। वहीं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) इससे संबंधित तस्वीरें भी आए दिन जारी कर



रहा है। इस बीच, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी अब एक खास तस्वीर साझा की है। नासा ने चंद्रमा की जिस सतह पर चंद्रयान-3 उत्तरा रहा था, उस जगह की तस्वीर साझा है।

### दक्षिणी ध्रुव से लगभग 600 किलोमीटर दूर है साइट

नासा ने सोशल मीडिया पर कहा कि चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से लगभग 600 किलोमीटर दूर है। लैंडिंग के चार दिन बाद एलआरओ ने लैंडर का एक टिएला ट्रॉफी द्वारा दर्शित किया गया था। नासा ने एक विवरण किया कि लैंडर के आरोप में यहां प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि स्टालिन पर सनातन धर्म को खत्म करने का आह्वान करने और खड़गे पर उनकी टिप्पणी का समर्थन करने के लिए मामला दर्ज किया गया है। एसपी ने एक विवरण दिया कि इस तरीके को देखने का असली मजा डें और सिवाय दंग के 37 ग्लास से आएगा। ये तरीके प्रज्ञान देने लैंडर से 15 मीटर दूर यानी करीब 40 फीट की दूरी से विलक की थी।

यह तस्वीर चंद्रमा पर ऐतिहासिक लैंडिंग के ठीक चार दिन बाद 27 अगस्त को चांद की कक्षा में धूम रहे। चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उत्तरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है।

विक्रम लैंडर 23 अगस्त को शाम 6 बजकर 4 मिनट पर चंद्रमा पर उत्तरा था। चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उत्तरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है।

## सुप्रीम कोर्ट ने लद्धाख पर्वतीय विकास परिषद के चुनाव की अधिसूचना रद्द की

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। लद्धाख पर्वतीय विकास परिषद के चुनाव की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (6 सितंबर) को रद्द कर दिया। लद्धाख पर्वतीय विकास परिषद के चुनाव 10

सितंबर को होने थे, सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान इस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। लद